Rajasthan Patrika- 08- November-2022

हर घर पहुंचेगा जल | सीवरेज नेटवर्क, तालाब एवं अन्य जलस्रोतों का होगा उन्नयन

6 हजार करोड़ से दूर होगी शहरों में पानी की किल्लत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. गांवों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी जलसंकट दूर करने का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। घर-घर नल से 24 घंटे जल पहुंचाने का लक्ष्य 2027 तक का है। इसके साथ ही सीवरेज नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा। दोनों नेटवर्क की क्षमता तीस वर्ष में शहर के विकास, आबादी के हिसाब से होगी।

प्रदेश के 413 निकायों में घर-घर नल से जल पहुंचाने के लिए 6240.50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक डीपीआर तैयार की गई है। इसके साथ में सीवरेज, नदी, तालाब एवं अन्य जल स्रोतों का भी उन्नयन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग से राशि खर्च की जाएगी। कुल मिलाकर सभी शहरों में पांच वर्ष के अंदर 12858.71 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इन सभी विकास कार्यों में केन्द्र और राज्य सरकार का भी हिस्सा रहेगा।

पेयजल सिस्टम **6240.50**
सीवरेज नेटवर्क **4957.01**
जल संरचना उन्नयन, पार्कों का विकास- **5589.38**
रिफार्म एवं अन्य व्यय- **1071.88**

(पांच साल में खर्च होने वाली राशि करोड़ रुपए में)

जलस्रोतों की व्यवस्था पहले होगी

निकायों को देखना होगा कि जिन जलस्रोत का निर्माण किया जा रहा है, उनमें पानी संचय की कितनी क्षमता है। आकलन करना होगा कि जिन जलस्रोतों से शहर में पानी की सप्लाई की जा रही है, उनमें एक वर्ष तक सप्लाई के लिए जल भराव है या नहीं। यदि पर्याप्त जल भराव नहीं है तो अन्य जलस्रोतों का विस्तार, गहरीकरण करना होगा।

ट्रीटमेंट प्लांट की अनिवार्यता

निकायों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की अनिवार्यता रखी गई है। इसके साथ ही सीवरेज से निकलने वाले मल जल को भी शुद्ध करने के बाद 30 फीसदी पानी की उपयोगिता और पानी की बिक्री की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सीवरेज के नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लान के रख-रखाव की जिम्मेदारी निकायों की होगी।

Hindustan- 08- November-2022

चेतावनी | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने 2002 से 2018 के सेटेलाइट डेटा के अध्ययन से निकाला निष्कर्ष, हिमालय से निकलने वाली नदियों में कम हो सकता है पानी

बर्फ तेजी से पिघली तो गंगा-यमुना की धरती पर जल संकट की आशंका

हि नेटवर्क

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। देश के उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में तापमान बढ़ोतरी के कारण बर्फ पिघलने की रफ्तार में तेजी आ गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि, तेजी से बर्फ पिघलने से कुछ वर्ष तो गंगा, यमुना समेत हिमालयी नदियों में पर्याप्त पानी रहेगा, लेकिन उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। इससे गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है।

उत्तरांचल विवि में आयोजित आकाशतत्व संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस) के वैज्ञानिकों ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के सेटेलाइट डाटा के विश्लेषण के आधार पर यह आशंका जताई है। 2018 से 2022 के सेटेलाइट डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि, हवा में गर्मी बढ़ने से बर्फ पिघलने की गति अत्यधिक तेज हो गई है। नवंबर से जनवरी-फरवरी तक हिमालय में 80% और मार्च से अप्रैल मई में 20% बर्फ ही टिक पा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमालय के निचले क्षेत्रों को सालाना 50 से 60 फीसदी पानी बर्फ पिघलने से, 15 से 16% पानी ग्लेशियर, 9 से 10 फीसदी बारिश और महज पांच फीसदी पानी भूजल से मिलता है।

"हिमालय में स्नो लाइन कवर 5 से 10 मीटर प्रति वर्ष पीछे खिसक रही है। स्नोलाइन कवर जहां सर्दियों में 1900-2000 मीटर क्षेत्र तक आ जाता है। जबकि, गर्मियों में 5000 मीटर से ऊपर तक पहुंच जाती है। इससे संकट संभव है।

-डॉ. मनीष मेहता, वरिष्ठ वैज्ञानिक